



कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी

प्रलिस के लयः

पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण मंजूरी ।

मेन्स के लयः

कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी और संबधति चतऱाँ ।

चरचा में क्योँ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कार्योत्तर (शुरू होने के बाद) पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearances-EC) स्वीकार्य है ।

- न्यायालय ने एक दावे के जवाब में नरिणय दया है कऱि **जैव-चकितिसा उपचार सुवधऱा** पर्यावरण मंजूरी के बऱिना स्थापति और चलाई गई थी तथा यह पर्यावरण में गरऱिवट पर चतऱा पैदा करती है ।

एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी (Ex Post Facto Environmental Clearance):

- कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी का तात्पर्य कऱिसे ऐसे उदयऱग या परयऱोजना के कामकाज की अनुमतऱ देना है, जसऱिने हरति मंजूरी प्रापत कयऱि बऱिना और परयऱोजना के संभावति पर्यावरणीय प्रभावों का खुलासा कयऱि बऱिना काम करना शुरू कर दया है ।
- सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने पाया कऱि **पर्यावरण (संरक्षण) अधनऱियम, 1986**, एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी को पूरी तरह से प्रतऱिबधति नहीं करता है ।
 - इसे नयऱिमति रूप से नहीं दया जाना चाहयऱि, लेकनऱि **असाधारण परसिथतऱियों** में सभऱि प्रासंगकऱि पर्यावरणीय कारकों को धयऱान में रखते हुए मंजूरी दी जा सकती है ।

संबधति चतऱाँ:

- कार्योत्तर मूल्यांकन **पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)** के मूल उददेश्य को वफऱिल कर देता है क्योँकऱि संचालन शुरू होने के साथ ही पारसिथतऱिकऱि कषतऱाऱि पहले ही हो चुकी होगी ।
 - संयुक्त राषट्र का **खादय और कषऱि संगठन (FAO)** EIA के उददेश्य को नरिणय नरऱिमाताओं, नयऱामक एजेंसयऱियों एवं परयऱोजनाओं के पर्यावरणीय परणऱामों के बारे में जनता को सचेत करने के रूप में परभऱाषति करता है "ताकऱि उन परयऱोजनाओं को संशोधति कयऱि जा सके, यदऱि आवशयक हो तो पर्यावरणीय गरऱिवट, नरऱिमाण त्रुटयऱियों से बचने और नकारात्मक दुषप्रभावों से होने वाले आरथकऱि नुकसान को रोकऱा जा सके ।
- उदयऱगों को मंजूरी के बाधऱा रहति परचऱालन के लयऱि प्रोत्साहति करने और अंततः जुर्माने की राशऱिका भुगतान करके वनऱियमति कयऱि जाने से, इसके उल्लंघनों के बढने एवं ऐसी सथति उत्पन्न होने की संभावना है, जहाँ पर्यावरण को होने वाली कषतऱाऱि अपरवऱिर्तनीय होगी ।

पर्यावरण प्रभाव आकलन:

- इसे पर्यावरण पर प्रस्तावति **गतवऱिधऱि/परयऱोजना के प्रभाव की भवऱिषयवाणी** के लयऱि अधयऱन के रूप में परभऱाषति कयऱि जा सकता है ।
- यह कुछ परयऱोजनाओं के लयऱि **पर्यावरण संरक्षण अधनऱियम, 1986** के तहत वैधानकऱि है ।
- **प्रकरऱियाऱि:**
 - नवऱिश के पैमाने, वकऱिास के प्रकार और वकऱिास के स्थान के आधार पर सकऱीनगऱि यह देखने के लयऱि की जाती है कऱि कऱिसी परयऱोजना को वैधानकऱि अधसऱिचनऱाओं के अनुसार पर्यावरण मंजूरी की आवशयकता है या नहीं ।
 - सकोपगऱि EIA के **संदरभ की शरतों (Terms of Reference -ToR)** का ववऱिरण देने की एक प्रकरऱिया है, जो कऱिसी परयऱोजना के वकऱिास में मुख्य मुददे या समस्याएँ हैं ।

- संभावित प्रभाव में परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं और इसके विकल्पों के पर्यावरणीय परिणामों का मानचित्रण शामिल है।
- EIA रिपोर्ट के पूरा होने के बाद प्रस्तावित विकास पर जनता को अनिवार्य रूप से सूचित और परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया:

- किसी परियोजना के लिये पर्यावरण मंजूरी (EC) प्राप्त करने के लिये एक EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- राज्य न्यायमकों द्वारा 'स्थापना के लिये सहमति (NOC)' जारी करने से पूर्व 'जन सुनवाई' की प्रक्रिया आयोजित की जाती है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंताओं पर विचार किया जाता है।
- EIA रिपोर्ट के साथ एक आवेदन पत्र जन सुनवाई एवं NOC के विवरण के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के समक्ष पर्यावरण मंजूरी के लिये प्रस्तुत किया जाता है एवं यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई परियोजना परियोजना A श्रेणी अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत आती है या वह परियोजना परियोजना B श्रेणी के अंतर्गत आती है।
 - श्रेणी ए परियोजनाओं को अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार वे स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं।
 - श्रेणी बी परियोजनाएँ एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरती हैं और उन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है।
 - श्रेणी B1 परियोजनाएँ (EIA अनिवार्य रूप से आवश्यक)।
 - श्रेणी B2 परियोजनाएँ (EIA आवश्यक नहीं होता)।
- तत्पश्चात् प्रस्तुत दस्तावेजों का विश्लेषण मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) द्वारा किया जाता है। समिति की सिफारिशों को अंतिम अनुमोदन या अस्वीकृति के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में प्रसंस्कृत किया जाता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (पीवाईक्यू)

????????

प्रश्न नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत सरकार को यह अधिकार देता है कि
2. पर्यावरण संरक्षण प्रक्रियाओं में जनभागीदारी की आवश्यकता और इसे प्राप्त करने की प्रक्रियाओं एवं विधियों का उल्लेख करना
3. विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिये मानक निर्धारित करना

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

??????:

सरकार द्वारा किसी परियोजना को मंजूरी दिये जाने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन तेज़ी से किये जाते हैं। कोयला पटिहेड्स पर स्थिति कोयले से चलने वाले थर्मल संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (2014)

प्रश्न. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2020 का मसौदा मौजूदा EIA अधिसूचना, 2006 से कैसे भिन्न है? (2020)

स्रोत: डाउन टू अर्थ